are banks in this country which have not recruited any staff since 1973. The National Industrial Teibunal, Bombay had laid down that the banks must maintain their staff and as their business and profits go up the staff should go up. Actually, many of these banks have reduced their staff. I can give one example. The ANZ Grindlays Bank had a staff of 4,800 in 1985. Today, they have a staff of only 2,595. This violates the verdict of the National Industrial Tribunal, Bombay. There are banks which are demanding that anybody opening an account must maintain an amount of Rs. 10,000 or Rs. 20,000. There are banks which charge a service charge of Rs. 100/- for any small transaction. Under the Contract Labour Act of India, banks cannot employ contract labour. But foreign banks are employing contract labour. This violates another law. The biggest objection is that there is no level-playing field where the banking industry is concerned. The Indian banks, whether nationalised or private, have certain social responsibilities as they have to invest so much in Government securities, they have to give concessional loans to agriculture, co-operatives, small-scale industries, etc., but no such condition is imposed on foreign banks. This makes for a very unlevel-playing field. This is very unfair for the Indian banks. I am surprised as to why the Government is so soft on the foreign banks.

Madam, I would like to draw the attention of this House to the fact that every year the foreign banks are repatriating profits to the tune of one thousand crores of repees in foreign exchange. This is a scandalous state of affairs and the Government of India and particularly the Ministry of Finance must do something about it.

RE-NEED FOR IMMEDIATE CENTRAL RELIEF FOR FAMINE HIT DISTRICTS OF UDAIPUR, DUNGARPUR AND BANSWARA

श्री सुन्दर सिंह भण्डारी (राजस्थान): उपसभापति महोदया, इस हाउस में, पहले भी बाढ़ के संबंध में चर्चाएं हुई हैं, लेकिन ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां सूखा है। खासतौर पर जब वनवासी क्षेत्रों में सूखे का सवाल खड़ा होता है तो समस्या बढ़ जाती है। मैं राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर के क्षेत्रों का विशेष उल्लेख करना चाहता हूं, जहां 78 परसेंट फसलें सूखे की वजह से नष्ट हो गई है। पीने के पानी की समस्या है, लोगों के पास रोजगार नहीं है। मुश्किल यह है कि सरकार के पास से इसी पिछली 28 तारीख को दो प्रकर के उत्तर मिले हैं। 28 नवम्बर को मौखिक प्रश्न सं० 22 के सवाल के जवाब में लोक सभा में यह बताया गया कि केन्द्रीय दल ने राहत और आवश्यकता का जायजा लेने के लिए राजस्थान का दौरा किया, लेकिन उसी दिन 225 नं० के लिखित सवाल के जवाब में यह कहा गया। जब यह पूछा गया कि क्या कोई वित्तीय सहायता की सिफारिश की गई है या कोई वित्तीय दल वहां भेजा गया या नहीं? उसका जवाब था, जी नहीं। अब इन दोनों में से कौन सा सवाल सही है? मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार इस क्षेत्र की तरफ चिन्ता करे, वहां के लोगों के लिए सरकार ने जो एडीशनल डिमांड की हुई है, उसके बारे में विचार करे।

जो सामान्य रूप से आपात सहायता कोष होता है सूखे इलाकों के लिए उसकी भी दूसरी और तीसरी किस्त नहीं गई है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि इस सूखाग्रस्त क्षेत्र में जो केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता है, वह भेजी जाए। वहां से जो रिपोर्ट आई है, उसमें जल्दी ही एडीशनल पैसे की डिमांड की गई, उसको जितनी जल्दी हो सके, पूरा किया जा सके, ताकि वहां के लोगों के लिए रोजी-रोटी का इंतजाम किया जा सके।

श्री सतीश अग्रवाल (राजस्थान): मैं माननीय भंडारी जी की इस मांग का पूर्ण समर्थन करता हूं।

RE:DEFILING OF AMBEDKAR STATUE AT BANGALORE

कुमारी सरोज खापर्डे (महाराष्ट्र): महोदया, मैं अत्यन्त दुखी मन से इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं एक ऐसी घिनौनी घटना की ओर, जिसने देश के पूरे दलित समाज को हिलाकर रख दिया है क्योंकि इस कांड के द्वारा दीलतों के मसीहा परम् पूज्य डा० बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करके सम्पूर्ण दलित समाज का अपमान किया है। यह जो दलित समाज की, अपमान करने की घिनौनी चेष्टा की गई है, यह अत्यन्त

दुखदपूर्ण घटना मैं महसूस कर रही हूं।

महोदया, घटना 13 नवम्बर, 1995 की है। जब बैंगलौर के डा॰ भीम राव अम्बेडकर मेडिकल कालेज के परिसर मे दलितों के मसीहा बनने वाले एक राजनैतिक-दल, जो राज्य मे सत्तारूढ़ है, एक मंत्री के बेटे ने पूजनीय डा॰ बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के ऊपर शराब उड़ेलकर, उन्हें गालियां दीं तथा दलित समाज के प्रति अपशब्दों का प्रयोग किया। यह अत्यन्त घृणित कार्य है, जो सार्वजनिक रूप से किया गया और जाहिर हैं कि यह जानबूझ कर किया गया। इस घटना के द्वारा न केवल डा॰ बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया गया बल्कि पूरे देश के दलित समाज का अपमान हुआ। इतना सब कुछ होने पर भी अपराधी के खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके विरोध में कर्नाटक में आज दलित समाज सड़कों पर आ गया है। यदि शीघ्र इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई और कलप्रिट को अगर पकड़ा नहीं जाएगा तो मुझे ऐसा डर लगने लगा है कि सारे देश में इसकी आग फैल जाएगी और सारे देश के दलित एकजुट होकर सड़क पर आ जाएंगे। इस प्रकार की बातें देश में फैल सकती हैं, दलित वर्ग विरोध कर सकता है।

अतः मेरी सरकार एवं इस महान सदन से मांग है कि दोषी के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए और इस जघन्य कांड की सार्वजनिक भर्त्सना करनी चाहिए।

महोदया, इन्ही शब्दों के साथ मैं आपके माध्यम से, सभापति महोदय ने मुझे जो परमीशन दी अपने विचारों को सदन में रखने के लिए, उनका धन्यवाद करती हूं। धन्यवाद।

श्री के॰ रहमान खान (कर्णाटक): मैडम, मैं एसोसिएट करता हूं।

†[شری کے۔ رحمان خان: میڈم میں ایسوسیئیٹ کرتا ہوں۔]

उपसभापतिः आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की है। ...(व्यवधान)...

श्रीमती सुषमा स्वराज (हरियाणा): सारा सदन संबद्ध करता है।

उपसभापतिः जी, सारा सदन संबद्ध करता है।

श्रीमती सुषमा स्वराजः इसलिए कि डा॰ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर किसी एक वर्ग के नहीं थे बल्कि पूरे हिन्दुस्तान के सम्मानीय थे और उनका अपमान राष्ट्र का अपमान है।

उपसभापतिः सब आपके साथ सहमत है। आपने यह एक महत्वपूर्ण सवाल यहां उठाया है। इस तरह की हरकत करने से बाबा साहब का अपमान नहीं होता है, वह तो उससे बहुत ऊपर हैं। सूरज को कहीं दिखाने से सूरज की रोशनी कम नहीं होती है। इस तरह से तो हम अपने देश का अपमान करते हैं, दुनियां में अपना अपमान करते हैं। इसका अर्थ यही निकलता है।

बाबा साहब इतने बड़े आदमी थे, उनके ऊपर कोई कुछ इस तरह का करेगा तो उन पर कुछ असर नहीं होता, उनको तो अच्छा काम करना था और वह करके चले गए, मगर हम कैसे उनकी इज्जत करते हैं, यह हमारे किरदार पर, हमारे करेक्टर पर है। इस तरह का करने से कितना बुरा असर पड़ता है, यह सोचना चाहिए। .....(व्यवधान)..

Such people who show disrespect in such a manner should be taken to task.

कुमारी सरोज खापर्डेः उपसभापति महोदया, मुझे बात समझ में नहीं आ रही कि मंत्री का बेटा, जिसने यह कृत्य किया है, उसके ऊपर अभी तक कार्यवाही क्यों नहीं वहां की सरकार कर रही? क्यों उसको संरक्षण दिया जा रहा है?

उपसभापतिः आपने खुद ही कह दिया। ..... (व्यवधान)..

मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी (उत्तर प्रदेश): मंत्री का बेटा है .....(व्यवधान)..

†[مولانا عبیداللہ خان اعظمی: منتری کا بیٹا ہے ۔۔۔ مداخلت ۔۔۔]

कुमारी सरोज खापर्डेः मंत्री का बेटा है तो सारे कसूर माफ हैं उसके?

मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मीः जी, मंत्री का सारा कसूर माफ, प्रधानमंत्री का सारा कसूर माफ। .....(व्यवधान)..

† Transliteration in Arabic script.

†

†[مولانا عبید اللہ خان اعظمی: ۔منتری جی کا سارا قصور معاف - پردھان منتری کا سارا قصور معاف ...(مداخلت)...]

कुमारी सरोज खापर्डे: सारे देश का संविधान जिसने लिखा, ऐसे व्यक्ति की प्रतिमा के साथ इस तरह का खिलवाड़ करने के बावजूद उस व्यक्ति के खिलाफ वहां की सरकार कुछ नहीं बोल रही।

मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी: इस देश की यही बात है कि जितने बड़े लोग हैं, उनकी बुराई को बड़ी बना कर माफ कर दिया जाता है।

†[مولانا عبید اللہ خان اعظمی: اس دیش کی یہی بات ہے کہ جتنے بڑے لوگ ہیں انکی برائی کو بڑی بنا کر معاف کر دیا جاتا ہے]

उपसभापतिः मौलाना ओबैदुलला खान आज़मी।

मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी: शुक्रिया, मैडम।

†[مولانا عبید اللہ خان اعظمی: شکریہ میڈم]

श्री सत्य प्रकाश मालवीयः आप बोल चुके हैं।

उपसभापतिः यह तो हर चीज पर बोल रहे हैं, तो भी बोलने ही दें।

SPECIAL MENTIONS

Need For Improvement in National Minorities financial Development Corporation

श्री मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी (उत्तर प्रदेश): मैं शुक्रगुज़ार हूं, मैडम, आपका कि आपने समय दिया। मैं आपके जरिए हाउस की तवज्जो माइनॉरिटीज फाइनेन्शियल डेवलपमेंट कारपोरेशन की तरफ मुतव्वजे करना चाहता हूं।

मैडम, मरकज़ी हुकूमत काफी लम्बे अरसे से ढिंडोरा पीट रही थी कि वह माइनॉरिटीज़ की फला-ओ-बहबूद के लिए एक माइनॉरिटी फाइनैंशियल डेवलपमेंट कारपोरेशन बनाएगी और माइनॉरिटीज़ की जिन्दगी में खुशहालियां रुनुमा होंगी। बहुत दिनों तक प्रपोगंडे के बाद 30 सितम्बर, 1994 को इसका रजिस्ट्रेशन करवाया गया और कहा गया कि इसकी मालियात 500 करोड़ रुपए होंगी। उसके बाद 1994 में हुकूमत ने कुछ नहीं किया और सो गई। बड़ी मुश्किल से 2 जनवरी, 1995 को हुकूमत को कारपोरेशन का चेयरमैन मिला और हिदायतुल्ला खान साहिब, साजिक़ कैबिनेट मिनिस्टर हुकूमते बिहार को इसका चेयरमैन मुकर्रर किया गया। उनको यकीन दिलाया गया था कि उनका दर्जा स्टेट मिनिस्टिर का होगा, लेकिन यह वायदा भी पूरा नहीं किया गया और उनकी हैसियत बोर्ड के हक डायरेक्टर की बनाकर रख दी गई। यह सब कुछ सोची-समझी साजिश के तहत किया गया ताकि कारपोरेशन कभी मुअस्सर ढंग से काम न कर सके और उसके नाम को प्रोपोगंडे के तौर पर इस्तेमाल भी कर लिया जाए। साथ ही साथ अकल्लियतों का भी भला न हो। अलबत्ता मुसलमानों को बंधुवा मजदूर बनाकर रखने की जो लोग नीयत मुल्क में फिरकापरस्ती के तहत रखते हैं, उन्हें यह कहने का जरुर मौका दे दिया गया कि इस तरह से हुकूमत मुसलमानों की मुंह भराई करती है। मोहतरमा सदर साहिबा, हुकूमत का कहना यह है कि कारपोरेशन का काम शुरू करने के लिए वेलफेयर मिनिस्ट्री ने 1994-95 में 50 करोड़ रुपए दिए हैं और इस साल के लिए 39 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। जो पैसा पिछले साल दिया गया था। वह सारा बेकार चला गया। कुछ खा-पी लिया गया, कुछ चहेतों में बांट दिया गया, आम आदमी उसके फायदे से महरूम हो गया। इसके अलावा एक धोखाघड़ी यह की गई है कि कारपोरेशन तो मरकज़ी हुकूमत का होगा लेकिन मरकज़ी हुकूमत उसमें सिर्फ 25 फीसदी रुपया देगी बाकी सूबाई हुकूमतें देंगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर मरकज़ी हुकूमत ने 500 करोड़ रुपए का मालियाती कारपोरेशन बनाया है तो आखिर सूबाई हुकूमतों पर इसकी जिम्मेदारी क्यों डाली गई है कि सूबाई हुकूमतें इस पैसे को दें? जाहिर है कि सूबाई हुकूमतें इस काम को नहीं करेंगी और मरकज़ी हुकूमत इस तरह से माइनॉरिटीज़ को जिस तरह पिछले दिनों धोखा देती आई है, अपनी धोखाघड़ी से बाज नहीं आएगी। यह अकल्लियतों के साथ बहुत खुला हुआ जुल्म है। अगर आपने सैंटर में मालियाती कारपोरेशन बनाया है तो सैंटर को ही इस 500 करोड़ रुपए को भी देना चाहिए।

अब जरा एक निगाह इस पर भी डाल ली जाए कि सूबाई हुकूमतें कितना तावुन कर रही हैं तो हालात तशवीशनाक भी है और शर्मनाक भी। सिर्फ यू॰पी॰ की हुकूमत ने 6 करोड़ 95 लाख रुपए मुहैया कराए हैं, हुकूमते केरल ने एक करोड़ का वायदा किया है, बिहार और आंध्र ने भी कुछ देने का वायदा किया है। हुकूमते महाराष्ट्र का साफ इंकार आपके सामने है। वह 25 फीसदी भी अपनी फिरकापरस्ती और दादागिरी के ज़रिए हज़म कर गई है और उसका कहना यह है कि हम एक नया पैसा भी इसमें नहीं देंगे। बाकी हुकूमतें अंधी, गूंगी

†Transliteration in Arabic script.